पेज थ्री देहरादून

देहरादून बृहस्पतिवार 2 अप्रैल 2020 पेज 8

लॉकडाउन के दौरान समाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग।

हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

सीएम राहत कोष में विधायक कंडारी ने दिया एक माह का वेतन

संवाददाता देहरादून। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने कोरोना वायरस से बचाव हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता राशि के रूप में एक माह का वेतन दिया है। कोविड–19 के दृष्टिगत उत्तराखंड बीज प्रमाणीकरण संस्था देहरादून, द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में रु. 51 लाख की धनराशि दी गई है। यह जानकारी अध्यक्ष, उत्तराखंड बीज प्रमाणीकरण संस्था, राजवीर सिंह ने दी। पूर्व अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुण कुमार सूद ने भी रु. 11 हजार की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है।

जजा. कल्याण निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारी एक दिन का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे

संवाददाता देहरादून। कोविड–19 के दृष्टिगत जनजाति कल्याण निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाएगा। यह जानकारी निदेशक जनजाति कल्याण सुरेंद्र चंद्र जोशी द्वारा दी गई। कोविड–19 के दृष्टिगत नुनावाला निवासी यशवंत सिंह रावत ने रु. 2 लाख का चेक एवं मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह रावत ने रु. 21 हजार का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु दिया है।

मोदी भोजन का शुभारंभ

संवाददाता देहरादून। राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र के विधायक खजानदास एवं शहर के महापौर सुनील उनियाल गामा के द्वारा मोदी भोजन का शुभारंभ कनौजिया भवन से किया गया। इस अवसर पर जिसमें महानगर के जिला मंत्री एवं विधानसभा के प्रभारी सुनील शर्मा, हरीश डोरा एवं करनपुर मंडल के अध्यक्ष विजय थापा, अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष विशाल गुप्ता के द्वारा राजपुर रोड क्षेत्र के भोजन के पैकेटों का वितरण किया गया।

कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण को की जा रही तैयारियों की जानकारी ली

संवाददाता देहरादून। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डा हरक सिंह रावत द्वारा आज जनपद मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों, बीडीओ, स्वास्थ्य अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों से कोरोना वायरस (कोविड–19) के रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। इस अवसर पर मंत्री द्वारा जनपद पौड़ी गढवाल में सभी आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने, खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण उपलब्धता रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कडाई से पालन करने हेतु समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये गया।

परिवहन से जुड़े इन दस्तावेजों में छूट से बड़ी राहत

संवाददाता देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की समय सीमा को बढाए जाने से जनता को बड़ी राहत मिली है। इसके मुताबिक अब एक फरवरी और उसके बाद समाप्त होने वाले दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माना जाएगा। यानी इस अवधि का उनसे कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन दस्तावेजों में सभी तरह के फिटनेस परमिट, लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज आदि शामिल हैं। इसके साथ ही संचालन न होने की दशा में व्यावसायिक वाहनों को छूट देने को भी संबंधित परिवहन मुख्यालयों को कहा गया है। अब मुख्यालय तय करेगा कि टैक्स में छूट कितने समय के लिए दी जाए। प्रदेश में लॉकडाउन के बाद से ही जरूरी वस्तुओं के परिवहन को छोड़ शेष व्यवसायिक वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद है। इसके अलावा विभागों में भी कर्मचारियों के न होने के कारण कई कार्य प्रभावित हैं। अभी केवल बीएस फोर श्रेणी के वाहनों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा था, लेकिन बीते रोज ही केंद्र ने इस पर भी रोक लगा दी थी।

वहीं, परिवहन व्यवसायियों के सामने आ रही कठिनाइयों को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाइसेंसों के नवीनीकरण करने की सीमा एक माह बढ़ाने की घोषणा की थी। इस संबंध अब केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है।

उत्तराखंड में अवैध रूप से घुस रहे 13 जमातियों को पकड़ा

हडकंप

संवाददाता

देहरादून। निजामुद्दीन मरकज में शामिल जमात के लोग देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने में कैरियर बन रहे हैं। ये लोग मरकज से लौटकर देश के अलग–अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। पुलिस–प्रशासन इनको चिन्हित कर स्वास्थ्य जांच कराने के बाद क्वारंटाइन कर रहा है। वहीं इनके जाहिलियत की हद ये है कि ये खुद सामने आने की बजाय छिप रहे हैं। और तो और बुधवार को चोरी छिपे जमात से लौटकर 13 लोग रुद्रपुर के रास्ध्ते रेलवे ट्रैक पकडकर उत्ध्तराखंड में घुस रहे थे। रुद्रपुर स्ध्टेशन पर रेलवे पुलिस ने इनको देखा तो पुलिस को सूचना दी।

जमातियों के चोरी छिपे उत्तराखंड में घुसने की सूचना पर पर हडकंप मच गया। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर टीम के साथ पहुंचे एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा, सीओ अमित कुमार, कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट पुलिस टीम जमातियों से पूछताछ की। प्राथमिक स्ध्वास्ध्थ्य जांच कराने के बाद सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी जमाती हल्द्वानी आजाद नगर निवासी के निवासी हैं।

एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि रेलवे पुलिस ने सूचना दी कि कुछ लोग ट्रैक पकडकर जा रहे हैं। जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सभी उन्हें रोक लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि बीते दिनों वे रामपुर में आयोजित जमात में शरीक होने गए थे। परिवहन की सुविधा ठप होने के कारण रेलवे ट्रैक के सहारे हल्द्वानी के लिए निकले थे। उन्होंने बताया कि कुल 13 लोग आए हैं। मौके पर जब पहुंचे तो नौ लोग ही मिले थे। चार भागने की कोशिश कर रहे थे। जिन्हें आगे कुछ दूर जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी के स्वास्थ्य का परीक्षण कराकर पंतनगर स्थिति क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। फिलहाल इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि ये लोग दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे या नहीं। पुलिस भी इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रही है।

पुलिस–प्रशासन इनको चिन्हित कर स्वास्थ्य जांच कराने के बाद क्वारंटाइन कर रहा है

रुद्रपुर में फरवरी में आए थे जमात के लोग

दिल्ली के तब्लीगी जमात के 50 लोग फरवरी के अंतिम सप्ताह में उधम सिंह नगर भी आए थे। हालांकि मार्च में चले गए। जमात के लोग जिले में कहां कहां गए थे, किससे मिले थे। इसकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी है। दिल्ली से फरवरी के अंतिम माह में जमात के करीब 50 लोग आए थे। इसके बाद लोग चले गए थे। ऐसे में पुलिस और खुफिया विभाग उधमसिंहनगर आए जमात के लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि ये लोग इस बीच किस किस के संपर्क में आये थे। एसएसपी बरिन्द्रजीत सिंह ने बताया कि फरवरी में आए जमात के लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए पुलिस और खुफिया विभाग जुटी है।

उत्तराखंड से यहां से निजामुद्दीन तब्लीगी मरकज में शामिल

दिल्ली में 12 से 14 मार्च को निजामुदीन में तब्लीगी जमाती मरकज आयोजित हुआ था। जिसमें रामनगर गुलरघट्टी व खताड़ी क्षेत्र से नौ लोग और रानीखेत से चार लोग शामिल हुए थे। चेकअप के बाद उन्हें ग्राम छोई स्थित एक रिसोर्ट में 14 दिन तक क्वारनटाईन में रखा गया है।

लॉकडाउन के बीच पैरोल ने बढ़ाई पुलिस की चुनौती

चुनौती

- दूसरे प्रदेशों के 169 कैदियों को घर छोड़ना बड़ी चुनौती

देहरादून। **संवाददाता**

जेल प्रशासन ने कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए कैदियों के बीच सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाने के लिए कैदियों की रिहाई शुरू कर दी है। हालांकि, अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती दूसरे प्रदेशों के कैदियों को छोड़ने की है। राज्य की जेलों से कुल 716 कैदियों को छोड़ा जाना है।

पहले चरण में 610 कैदियों को छोड़ा जा रहा है। इनमें 441 कैदी उत्तराखंड और 169 दूसरे प्रदेशों के हैं। अब पुलिस के सामने चुनौती इन्हीं 169 कैदियों को इनके घरों तक छोड़ने की है। जेलों में कोरोना के फैलने की आशंका के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले स्वतरू संज्ञान लिया था और प्रदेश सरकारों से जेलों में बंद सात साल से कम सजा वाले और विचाराधीन कैदियों को बेल अथवा पैरोल पर छोड़ने का निर्देश दिया। इस क्रम में उतराखंड में भी एक समिति का गठन कर कैदियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। दरअसल, उत्तराखंड की 11 जेलों में 3420 कैदी रखने की क्षमता है मगर यहां 5800 कैदी बंद हैं। इनसे से परीक्षण के बाद 716 कैदियों को छोड़ने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 610 कैदियों की रिहाई की जा रही है। इनमें दूसरे प्रदेशों के कैदी भी शामिल हैं और यही कैदी पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। दरअसल, इन कैदियों को पुलिस ने इनके घरों तक छोड़ना है।

प्रदेश में लॉकडाउन हैं और सीमाएं सील हैं। चूंकि इनकी संख्या खासी अधिक है तो इनके साथ उतना ही पुलिस बल भी चाहिए होगा। उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है इस कारण पुलिस को इन्हें छोड़ने के लिए वाहनों के साथ ही सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी है।

कैदियों की निगरानी भी करनी होगी

कोरोना वायरस संक्रमण के चलते कैदियों के छह माह के पैरोल पर रिहा होने से पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। लॉकडाउन का पालन कराने के साथ–साथ पुलिस को इन कैदियों की निगरानी भी करनी होगी। जिला कारागार के 43 कैदियों सहित अभी तक हरिद्वार जिले के 60 से अधिक कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा चुका है।

सामान खत्म होने का डर दिखा वसूल रहे ज्यादा कीमत

संवाददाता रुड़की। प्रशासन के सख्त रुख के बाद भी मुनाफाखोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सामान खत्म होने का डर दिखाकर लोगों से ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। हैरानी की बात ये है कि प्रशासन की ओर से जारी की गई रेट लिस्ट में पहले ही कई वस्तुओं के दाम बढ़ाकर लिखे गए हैं। ऐसे में दुकानदारों को और मनमानी का मौका मिल गया है। लॉकडाउन के बीच खाने–पीने की वस्तुओं के दाम काफी बढ़ गए है। बिना ब्रांड का चक्की से मिलने वाला आटा 21 मार्च से पहले तक रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में 25 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, लेकिन प्रशासन ने ही रेट बढ़ाकर 32 रुपये रखे हैं। इसी तरह से चीनी के दाम 36 रुपये प्रति किलोग्राम थे। प्रशासन ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम दाम रखे हैं। वर्तमान में सभी जगह चीनी 38 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून
ही मान्य होगा।